निर्णायक संघर्ष हेतु तिब्बत समर्थक तैयार

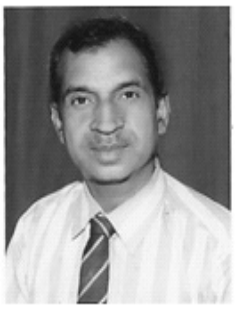

निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे द्वारा वर्ष 2013 को ''तिब्बतन सोलिडरिटी कैम्पेन'' के रूप में मनाये जाने का निर्णय स्वातयोग्य है। चीन में नए राजनीतिक नेतृत्व को इस निर्णय के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। अभी भी तिब्बत में जारी दमन के विरोध में तिब्बतियों द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण आत्मदाह का सिलसिला जारी है। वे मांग कर रहे हैं कि चीन सरकार तिब्बत से अपने अवैध कब्जे को समाप्त करे। उनकी मांग यह भी है कि परमपावन दलाई लामा जी को ससम्मान तिब्बत लाया जाये। इन दोनों मांगों के समर्थन में तिब्बत में रह रहे तिब्बती एकजुट हैं। इसीलिए वे आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठाकर अपना बलिदान कर रहे हैं। उनकी शहादत तिब्बत की आजादी के लिए है। वे अपनी शहादत से पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि शांतिप्रिय तिब्बत में चीन की सरकार व्यापक पैमाने पर मानवाधिकारों का तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रही है।

तिब्बत में जारी चीन सरकार के उत्पीड़न के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनमत एवं जनसमर्थन लगातार बढ़ने लगा है। उम्मीद है कि तिब्बतन सोलिडरिटी कैम्पेन से यह समर्थन तिब्बत पर चीन के अवैध नियंत्रण के खिलाफ निर्णायक एवं सुनियोजित संघर्ष में परिणत हो जाएगा। इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को अब टाला नहीं जा सकता।

दिल्ली में 30 जनवरी से प्रारम्भ ''तिब्बती जन एकजुटता अभियान'' चीन के नए नेतृत्व को चिंतित किए हुए है। सारे तिब्बत समर्थक संगठन चीन के खिलाफ शंतिपूर्ण संघर्ष के लिए तैयार हैं। ज्ञातव्य है कि 30 जनवरी महात्मा गांधी का शहादत दिवस है। परमपावन दलाई लामा और तिब्बत की निर्वासित सरकार महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुरूप सत्य–अहिंसा पर आधारित शंतिपूर्ण संघर्ष के पक्षधर हैं। वे चीन सरकार के अमानवीय, अलोकतांत्रिक तथा पाशविक उत्पीड़न के विरूद्ध शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। तिब्बत सरकार के मंत्री और निर्वाचित जन प्रतिनिधि तिब्बती जन एकजुटता अभियान द्वारा तिब्बत की आजादी की लड़ाई को और भी व्यापक बनाने वाले हैं।

तिब्बती जन एकजुटता अभियान का जोर चीन को बेनकाब करने पर है। चीन ऐतिहासिक तथ्यों को विकसित करके तिब्बत को अपना अंग बताता आ रहा है। वह तिब्बत में जारी उत्पीड़न को प्रशासनिक सुधार तथा तिब्बत के विकास का नाम दे रहा है। सच्चाई यह है कि इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था और फिर से वह आजाद होकर रहेगा। इस समय चीनी नेतृत्व के लिए तिब्बत समस्या को सुलझाने का अच्छा अवसर है। दलाई लामा जी की तरह प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे भी तिब्बत के लिए केवल ''वास्तविक स्वायत्तता'' की मांग कर रहे हैं। वे चीन के अधीन तिब्बत को रखना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक स्वायत्तता के साथ। चीन को यह मांग मान लेनी चाहिये अन्यथा बाद में उसे पूरी तरह तिब्बत को आजाद करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

चीन को हिंसक आंदोलन का भी सामना करना पड़ सकता है। अनेक तिब्बती और तिब्बत समर्थक इस विचार के हैं कि चीन के अवैध नियंत्रण को समाप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेना होगा। उन्हें लगता है कि चीन की सरकार शांतिपूर्ण संघर्ष को निर्ममतापूर्वक कुचल रही है। वर्तमान तिब्बती नेतृत्व अहिंसा का समर्थक है इसलिए आंदोलनकारी शांति एवं अहिंसा के संकल्पों से बंधे हुए हैं। चीन सरकार द्वारा इस तथ्य की लगातार उपेक्षा संघर्ष को हिंसक बना देगी।

दलाई लामा लगातार भगवान बुद्ध के दर्शन को अपनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार–प्रसार कर रहे हैं। बुद्ध का दर्शन शंति, करूणा, मैत्री, अहिंसा और सद्भाव का दर्शन है। वे स्वयं चीन के लोगों के प्रति भी इसी प्रकार के भाव रखते हैं। पटना में हाल ही संपन्न अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में उन्होंने शंति–अहिंसा को अपनाने पर जोर दिया। ज्ञातव्य है कि उस सम्मेलन में बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार समेत बिहार के अनेक मंत्री एवं अधिकारी उपस्थित थे। दुसरे पंथों–सम्प्रदायों के धर्मगुरू भी उनके साथ विचार–विनिमय में शामिल हो रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग के 2013 के महाकुंभ मेले में उन्हें देखने–सुनने के लिए उमड़ने वाली भारी भीड़ इसी का सबूत है कि लोग उनके विचारों से सहमत हैं।

अभी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर विश्वभर में तिब्बत समर्थक संगठनों ने दलाई लामा के आदर्शों के प्रति अपनी वैचारिक एकजुटता प्रकट की। भारत में उनसे मिलने विश्व के सभी देशों के लोग आते रहते हैं। इसी प्रकार विश्व के अधिकांश देशों में उन्हें सादर निमंत्रित किया जा रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि चीन सरकार भी उन्हें अपना मित्र समझकर उनके प्रति सम्मान प्रकट करे तथा तिब्बत को ''वास्तविक स्वायत्तता'' प्रदान करने हेतु निर्वासित तिब्बती सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण वार्ता करे। भारत सरकार इस दिशा में पहल करे तो ठीक रहेगा, क्योंकि चीन के अवैध नियंत्रण के पहले स्वतंत्र तिब्बत वस्तुतः भारत एवं चीन के बीच एक बफर स्टेट (मध्यस्थ राज्य) था। तिब्बत समस्या के समाधान से भारत के राष्ट्रीय हित ज्यादा सुरक्षित होंगे और चीन के साथ भारत के संबंध भी सुदृढ़ होंगे।

प्रो. श्यामनाथ मिश्र

पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राज.)

मो.–9829806065 | 8764060406

E-mail & facebook: shyamnathji@gmail.com

दलाई लामा ने तिब्बत में आत्मदाह के मामलों की जांच पर जोर दिया

(फायूल, 7 जनवरी, 2013)

परमपावन दलाई लामा ने तिब्बत के भीतर जारी आत्मदाह की लहर के पीछे कारणों की 'व्यापक जांच' करने का फिर से आह्वान किया है। दलाई लामा एनडीटीवी पर रविवार (6 जनवरी) की रात टाक शो 'योर कॉल' में आए हुए थे। तिब्बती आध्यात्मिक नेता ने कहा, "पिछले साल, जब यह (आत्मदाह) पहली बार हुआ था, तो मैं जापान में था और मैंने कहा था कि अब समय आ गया है कि चीन सरकार इसकी व्यापक जांच करे और इन दुःखद घटनाओं के कारणों की जांच करे। ये घटनाएं कुछ वजहों के लक्षण हैं।"

उन्होंने कहा कि तिब्बत के भीतर रहने वाली तिब्बतियों की दो से तीन पीढ़ियां वास्तव में चीन के शासन के तहत "काफी पीड़ित रही हैं।" वर्ष 2009 से अब तक 95 तिब्बतियों ने चीनी कब्जे के विरोध में और आज़ादी तथा परमपावन दलाई लामा की वापसी की मांग करते हुए खुद को आग लगा लिया। हजारों तिब्बती व्यापक विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं, लेकिन चीनी अधिकारियों ने अपनी दमनकारी नीतियों को और बढ़ा दिया है और आत्मदाह की घटनाओं के आसपास सख्ती और बढ़ा दी है।

इस सवाल पर कि क्या वह आत्मदाह रोकने के लिए अपील करेंगे, दलाई लामा ने कहा कि निर्वासित तिब्बती प्रशासन ने कभी भी विरोध प्रदर्शनों को प्रोत्साहित नहीं किया है।

77 वर्षीय तिब्बती नेता ने कहा, "यह सवाल राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। (तिब्बती) राजनीतिक नेताओं ने शुरुआत से ही बहुत साफतौर पर कहा है कि हमने इस तरह की कार्रवाई को कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया है, लेकिन यदि अब भी हमें उनसे (आत्मदाह करने वालों से) कुछ कहने का मौका मिलता तो मैं यही कहता कि 'आपको यह नहीं करना चाहिए।' तो उनसे कुछ कहने के लिए मुझे उनको कोई संदेश देने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिलता। मुझे बहुत दुःख होता है, मैं प्रार्थनाएं करता हूं, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता।

दलाई लामा ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के लिए उन पर आरोप लगाने के चीन सरकार के दांवपेच से समस्या नहीं सुलझने वाली। उन्होंने चीनी नेताओं से आग्रह किया कि तिब्बत संकट के बारे में "ज्यादा गंभीरता से सोचें"।

चीन के नए नेता शी जिनपिंग के बारे में जब उनकी उम्मीद के बारे में सवाल किया गया तो तिब्बती आध्यात्मिक नेता ने कहा कि "अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी।" और उन्होंने कहा कि नए नेताओं को अपने हितों की खातिर ज्यादा यथार्थवादी रवैया अपनाना होगा।

दलाई लामा ने कहा, "बल का प्रयोग करना पुराने जमाने का चलन है। ज्यादा हिंसा, ज्यादा दमन, ज्यादा असंतोष, यह अतार्किक है। इसलिए मुझे पर्याप्त भरोसा है कि नया चीनी नेतृत्व तथ्यों से सच्चाई जानना चाहेगा और देर–सबेर ज्यादा यथार्थवादी रवैया अपनाएगा।"

क्या उन्हें तिब्बत को कभी एक आज़ाद देश के रूप में देखने की संभावना नजर आती है, इस बारे में सवाल पर परमपावन ने कहा, "यद्यपि ऐतिहासिक रूप से तिब्बत एक स्वतंत्र देश रहा है, लेकिन अब भविष्य की ओर देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है।"

"बल का प्रयोग करना पुराने जमाने का चलन है। ज्यादा हिंसा, ज्यादा दमन, ज्यादा असंतोष, यह अतार्किक है। इसलिए मुझे पर्याप्त भरोसा है कि नया चीनी नेतृत्व तथ्यों से सच्चाई जानना चाहेगा और देर–सबेर ज्यादा यथार्थवादी रवैया अपनाएगा।"

नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नेता ने कहा, "जी हां, हम एक अलग देश है, लेकिन हमें अनिवार्य रूप से इस पर जोर नहीं देना चाहिए। पहले एक नए तरह का वाजिब संघ बनाने की कोशिश करते हैं। यदि यह विफल रहता है तो कुछ अलग सोचना होगा।"

परमपावन ने कहा कि निर्वासित तिब्बती प्रशासन की नीति मध्यम मार्ग की है जिसमें तिब्बत के लिए वास्तविक स्वायत्तता की मांग की गई है और इसे अब तक चीनी जनता की तरफ से काफी समर्थन मिला है।

दलाई लामा ने कहा, "भावनात्मक रूप से बहुत से युवा लोग कहते हैं, 'हां हम आज़ादी चाहते हैं.' लेकिन उन्होंने हमें कभी यह नहीं दिखाया कि कदम–दर–कदम आज़ादी कैसे हासिल की जाए।" उन्होंने कहा, "चीनी जनता से कितना समर्थन मिलता है? भारत सरकार से कितना समर्थन मिलता है? यूरोपीय संघ से कितना समर्थन मिलता है? अमेरिका से कितना समर्थन मिलता है? यथार्थवादी तरीके से इन सबके बारे में सोचना महत्वपूर्ण है।"

हू जिनताओ के शासन में चीन–तिब्बत वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुईः लोदी ग्यारी

(फायूल, 1 जनवरी, 2013)

परमपावन दलाई लामा के पूर्व विशेष दूत लोदी ग्यालत्सेन ग्यारी ने कहा है कि चीन के साथ बाधित वार्ता प्रक्रिया में एक दशक तक राष्ट्रपति रहे हू जिनताओ के कार्यकाल में कुछ खास प्रगति नहीं हो पाई।

उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि हू के आने के बाद वार्ता की प्रक्रिया और सुस्त हुई है। हू 1989 में जब तिब्बत के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख थे तो उन्होंने तिब्बत में सैनिक शासन की घोषणा कर दी थी और यह 419 दिनों तक चला था। श्री ग्यारी धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार के मुख्यालय में चीन में नेतृत्व परिवर्तन के निहितार्थ पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

चीन के साथ बातचीत में करीब तीन दशक का अनुभव रखने वाले लोदी ग्यारी ने इस बात पर जोर दिया कि चीन के साथ वार्ता परमपावन दलाई लामा के नाम और उनकी भूमिका के बगैर संभव नहीं हो सकती। तिब्बती आध्यात्मिक नेता ने वर्ष 2011 में अपनी पूरी राजनीतिक सत्ता निर्वाचित तिब्बती नेतृत्व को सौंप दी थी।

पिछले साल इस्तीफा देने से पहले इस पूर्व विशेष दूत ने 2002 से 2010 के बीच नौ दौर की वार्ता का नेतृत्व किया था। उन्होंने कहा कि चीन के साथ निपटने में वार्ता के मुख्य लक्ष्यों में संगतता बनाए रखना जरूरी है।

लोदी ग्यारी और विशेष दूत के सांग ग्यालत्सेन ने तिब्बत के भीतर लगातार बिगड़ रही स्थिति और चीन की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने की वजह से ''हताश होकर'' मई, 2012 में इस्तीफा दे दिया था।

तिब्बत को इस उम्मीद में नहीं बैठना चाहिए कि चीन में कोई बदलाव आएगा, बीजिंग में किसी दृष्टि वाले नेता के न होने से तिब्बत पर कोई महत्वूपर्ण निर्णय लेने के लिए माहौल अनुकूल नहीं है।

इस विचार पर संदेह जताते हुए कि चीन में लोकतंत्र से तिब्बत मसले को हल करने में मदद मिलेगी, लोदी ग्यारी ने कहा कि तिब्बत को इस उम्मीद में नहीं बैठना चाहिए कि चीन में कोई बदलाव आएगा, बीजिंग में किसी दृष्टि वाले नेता के न होने से तिब्बत पर कोई महत्वूपर्ण निर्णय लेने के लिए माहौल अनुकूल नहीं है।

चीन के नए नेता शी जिनपिंग के तहत वार्ता प्रक्रिया का क्या भविष्य हो सकता है, इस सवाल पर पूर्व विशेष दूत ने कहा कि वह इस मामले में आशावादी हैं, इन खबरों को देखते हुए कि शी की कार्यशैली पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन से मिलती–जुलती है जो तिब्बत में रुचि रखते थे।

लोदी ग्यारी ने कहा कि अन्य किसी सक्षम विकल्प की गैर मौजूदगी में तिब्बत के लिए बस आगे एक ही रास्ता बचा है कि चीन के साथ वार्ता प्रक्रिया पर चलते रहा जाए।

तीन दिन के इस सम्मेलन का आयोजन 28 से 30 दिसंबर तक केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के तिब्बत नीति संस्थान द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का विषय थाः चीन में नेतृत्व परिवर्तन पर चीनी विद्वानों का सम्मेलनः चीनियों, तिब्बतियों और अन्य पर इसका निहितार्थ।

तिब्बती कार्यदल ने तिब्बत और चीन के नए नेताओं के बारे में चर्चा की

(तिब्बत सन डॉट कॉम, 2 जनवरी)

वार्ता पर तिब्बती कार्यदल के सदस्यों ने धर्मशाला में 31 दिसंबर, 2012 से 1 जनवरी, 2013 तक दो दिवसीय बैठक की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग (प्रधानमंत्री) लोबसांग सांगे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तिब्बत के गहराते राजनीतिक संकट की समीक्षा की गई, खासकर आत्मदाह की दुःखद लहर के बारे में। इस बैठक में इस बात की तात्कालिक आवश्यकता पर चर्चा हुई कि चीन के रिश्ते में तिब्बत की स्थिति क्या हो इसका एक शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए।

बैठक में शी जिनपिंग की अगुवाई वाले नए चीनी नेतृत्व के बारे में और तिब्बत मसले पर इसके निहितार्थ के बारे में भी चर्चा हुई। जिनपिंग मार्च में राष्ट्रपति हू जिनताओ की जगह राष्ट्रपति होंगे।

दलाई लामा के प्रतिनिधियों और चीनी नेतृत्व के बीच नौ दौर की वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकला है। इसके बाद वार्ता के लिए नियुक्त दो तिब्बती दूतों ने वार्ता में कोई प्रगति न होने की वजह से परेशान होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर भी कार्यदल ने वार्ता जारी रखने की बात कही है। लोदी ग्यारी और केलसांग ग्यालत्सेन ने वर्ष 2002 से ही वार्ता का नेतृत्व किया था और उन्होंने जून, 2012 में इस्तीफा दे दिया। कार्यदल की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई दलाई लामा के नए दूतों की नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए।

पिछले वर्षों में चीन ने दलाई लामा की व्यक्तिगत दर्जे के अलावा तिब्बती मसले के अन्य किसी भी पहलू पर चर्चा करने से इनकार किया है। वे यह स्वीकार करने से भी इनकार करते रहे हैं कि तिब्बत की राजनीतिक स्थिति का कोई मसला है और वे अब भी इस रुख पर कायम हैं।

चीन ने 1959 में तिब्बत पर कब्जा किया और इसकी वजह से दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी, जहां उन्होंने पहाड़ी कस्बे मैकलियोडगंज में निर्वासित तिब्बती सरकार का केंद्र बनाया। उन्होंने अपनी ''मध्यम मार्ग नीति'' के माध्यम से ''सार्थक स्वायत्तता'' के लिए आह्वान किया। दलाई लामा ने मई, 2011 में अपने राजनीतिक अधिकारों को त्याग दिया, लेकिन स्वायत्तता की उनकी नीति निर्वासित प्रशासन का विकल्प बनी रही। सिक्योंग लोबसांग सांगे के नेतृत्व वाला मौजूदा तिब्बती नेतृत्व अहिंसा और मध्यम मार्ग नीति के बारे में दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और उसका प्रबल रूप से यह मानना है कि संवाद ही तिब्बत मसले को हल करने का एकमात्र रास्ता है।

सांगे ने तिब्बतियों से अपील की है कि वे आत्मदाह जैसे चरम कदम न उठाएं। अब तक 90 से ज्यादा तिब्बतियों ने खुद को आग लगा लिया है, इस उम्मीद में कि इससे चीन ज्यादा आज़ादी देने की उनकी मांग पर गौर करेगा और निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को तिब्बत वापस आने दिया जाएगा।

कार्यदल का पुनर्गठन कर उसमें नए सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इस साल मार्च में राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सत्र में जब नए चीनी नेतृत्व को पूरी तरह से जिम्मेदारी मिल जाएगी तो उसके तुरंत बाद इस कार्यदल की एक बैठक बुलाई जाएगी।

जयपुर साहित्य समारोह में आकर्षण के केंद्र बने तिब्बती गुरु दलाई लामा

(प्रेट्र, जयपुर, 25 जनवरी)

जयपुर साहित्य समारोह में पूरे महफिल को अपनी तरफ आकर्षित कर लेने वाले दलाई लामा ने साहित्य की दुनिया में बौद्ध धर्म के असर के बारे में अपने व्याख्यान में इस बात पर जोर दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय के जमाने से ही ज्ञान के क्षेत्र में भारत का बहुत गहरा योगदान रहा है।

वर्ष 2005 में इस साहित्य समारोह की शुरुआत के बाद पहली बार आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को इसमें बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा, "भारत हमारा गुरु है और हमारे ज्ञान का समूचा स्रोत नालंदा से आता है।"

दर्शन और साहित्य पर बौद्ध धर्म के असर के बारे में सत्रों की शुरुआत करते हुए दलाई लामा ने भारत की तारीफ करते हुए कहा, "भारत इस बात का सजीव उदाहरण है कि किसी प्रकार विभिन्न धर्म और समुदाय सहअस्तित्व के साथ रह सकते हैं।

दलाई लामा ने जब अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता को आगे बढ़ाने में भारत की भूमिका के बारे में बात कही तो उनको खूब तालियां मिलीं।

उन्होंने कहा, "भारत की महानता अहिंसा के विचार में निहित है। यह देश दुनिया को देखने के लिए इस बात का सजीव उदाहरण है कि किस प्रकार शताब्दियों से यहां कई धर्मों का एक साथ अस्तित्व बना हुआ है।"

उन्होंने कहा, "धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरे धर्मों का सम्मान न करें। धर्मनिरपेक्षता के बारे में भारतीय समझ यह है कि सभी धर्मों का आदर करें और किसी को भी तरजीह न दें।" 77 वर्षीय तिब्बती नेता ने नैतिकता, शिक्षा प्रणाली और धर्मनिरपेक्षता जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बात की।

नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित दलाई लामा ने कहा, "भारत हमारा गुरु है और हम उसके चेला हैं। हम न सिर्फ आपके चेले हैं, बल्कि निष्ठावान भी हैं। हमारे पास जो भी ज्ञान है वह सब हमें भारत से मिला है।"

भारत की महानता अहिंसा के विचार में निहित है। यह देश दुनिया को देखने के लिए इस बात का सजीव उदाहरण है कि किस प्रकार शताब्दियों से यहां कई धर्मों का एक साथ अस्तित्व बना हुआ है।"

चीन की तिब्बत में पूरी तरह सूचनाओं की आवाजाही पर रोक लगाने की योजना, डिश एंटेना जलाए गए

(फायूल, धर्मशाला, 10 जनवरी, 2013)

पूर्वी तिब्बत के माल्हो में चीनी प्रशासन ने तिब्बतियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सैटेलाइट डिश एंटेना को जब्त करने के लिए व्यापक अभियान चलाया। पिछले महीने ''अवैध सैटेलाइट उपकरणों'' पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था।

तिब्बतियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ऐसे सैटेलाइट उपकरणों की मदद से ही विदेशी रेडियो और टीवी कार्यक्रम सुने जाते हैं और ये सरकार प्रायोजित दुष्प्रचार वाले समाचारों से इतर तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों को सही सूचनाएं मिलने के एकमात्र स्रोत हैं।

क्षेत्रीय प्रशासन ने 24 दिसंबर, 2012 को आठ बिंदुओं वाला एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए सभी ''अवैध सैटेलाइट उपकरण'' की बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर रोक लगा दी। यह चीनी शासन के खिलाफ हो रहे आत्मदाहों के बारे में सूचनाएं फैलने से रोकने के लिए सरकार के संचार पर व्यापक रोकथाम के प्रयासों के तहत की गई कार्रवाई थी। नोटिस के मुताबिक सैटेलाइट डिश वापस न करने वाले परिवारों पर 5,000 युआन (800 डॉलर) का जुर्माना लगाया जाएगा और जो लोग उपकरणों को जब्त करने के आधिकारिक कार्य में बाधा डालेंगे, उन पर भी या तो जुर्माना लगाया जाएगा या कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा।

रायटर्स की खबर के अनुसार पिछले महीने चीनी अधिकारियों ने 300 मठों से टेलीविजन जब्त कर लिए थे और उन सैटेलाइट उपकरणों को तोड़ दिया था जिनसे ''चीन विरोधी कार्यक्रमों'' का प्रसारण किया जाता है।

खबर के मुताबिक एक सरकारी अखबार में कहा गया है, ''इस महत्वपूर्ण समय में हुआंगनान प्रशासनिक क्षेत्र में सामाजिक स्थिरता कायम रखने के लिए हमें अपने कदमों को और मजबूत करना होगा और आत्मदाह के खिलाफ विशेष लड़ाई को पूरी तरह से लड़नी होगी।''

अमेरिका से प्रसारित होने वाली रेडियो सेवा रेडियो फ्री एशिया ने बुधवार को ऐसी तस्वीरें जारी कीं जिनमें ''सफाई अभियान'' के तहत चीनी अधिकारी सैकड़ों जब्त सैटेलाइट उपकरणों को नष्ट कर रहे हैं और जला रहे हैं।

आरएफए ने कहा कि यह अभियान रेबकोंग इलाके (चीनी तोंगरेन) तक केंद्रित है जो कि हाल में आत्मदाह वाले विरोध प्रदर्शनों की उठी लहर का केंद्र रहा है। यह आत्मदाह चीनी शासन को खत्म करने, आज़ादी और निवार्सित तिब्बती आध्यात्मिक नेता परमपावन दलाई लामा की वापसी की मांग करते हुए किए जा रहे हैं।

आरएफए तिब्बती सेवा से इस इलाके के एक सूत्र ने कहा, ''जिन लोगों के पास सैटेलाइट उपकरण पाए जा रहे हैं उन पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। तिब्बती लोग रेडियो फ्री एशिया और वायस ऑफ अमेरिका के कार्यक्रमों को सुनने के लिए भी इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। यदि कोई इस बात की सूचना देता है कि किसी अन्य के पास विदेशी कार्यक्रमों को सुनने वाले सैटेलाइट या रेडियो उपकरण हैं तो उसे 10,000 युआन का ईनाम दिया जाएगा।''

पिछले महीने हुई कठोर कार्रवाई की खबर देते हुए हफिंगटन पोस्ट ने कहा है कि आगे क्षेत्रीय अधिकारियों की योजना ''हर उस दुकान को रजिस्टर्ड करने की है जो सैटेलाइट सिग्नल रिसीव करने वाले उपकरण बेचते हैं और मठों की डॉर्मिटरी में लगे 3,000 टीवी सेटों को भी हटाने की तैयारी है।'' आरएफए की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऐसे छोटे सैटेलाइट डिश और नए रिसीवर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनसे सिर्फ सरकार नियंत्रित कार्यक्रमों को सुना जा सके।

नवंबर माह में माल्हो के चीनी अधिकारियों ने आत्मदाह विरोध प्रदर्शनों से जुड़े ''अपराध का खुलासा'' करने वालों को नकद ईनाम देने की घोषणा की है और चेतावनी देते हुए कहा गया कि जो लोग ''इस तरह के अपराधों में शामिल रहे हैं'' वे खुद को अंदर कर दें।

चीन के संयम बरतने और अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा बार–बार अनुरोध करने के बावजूद चीन ने आत्मदाह विरोध प्रदर्शनों पर अपना रवैया सख्त कर दिया है और सख्त उपायों की घोषणा की है जिनमें यह भी कहा गया है कि आत्मदाह के लिए सहयोग करने या उकसाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किया जाएगा।

'दलाई गुट' के खिलाफ लड़ाई जारी रखा जाएगाः चीनी नेतृत्व

(पीटीआई, बीजिंग, 8 जनवरी)

चीन ने दलाई लामा और उनके समर्थकों से मुकाबला करने का संकल्प लिया है ताकि अशांत तिब्बती इलाके में 'अनुकूल' सामाजिक और राजनीतिक वातावरण तैयार हो सके। चीन ने बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों से देशभक्त बनने और कानून का पालन करने को कहा है।

चीन पर शासन करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की नवगठित सात सदस्यीय स्थायी समिति के सदस्य यु झेंगशेंग ने दक्षिण–पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत का दौरा किया, जहां उन्होंने पहली बार तिब्बत पर बोला। इस प्रांत में चीनी शासन के खिलाफ आत्मदाह की व्यापक लहर चल रही है। झेंगशेंग ने कहा, "दलाई गुट के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी ताकि आर्थिक विकास और लोगों के कल्याण कार्यक्रमों में सुधार के लिए एक अनुकूल सामाजिक और राजनीतिक माहौल तैयार हो सके।"

उन्होंने भिक्षुओं और भिक्षुणियों से कहा कि वे देशभक्त बनें और उन्होंने सिचुआन प्रांत की जांच के दौरान कानून और मठ नियमों का मूल्यांकन किया।

तिब्बत में पिछले दिनों में आत्मदाह का सिलसिला सा चल पड़ा है जिसके बाद किसी नवनिर्वाचित चीनी नेता की यह पहली टिप्पणी है। विदेशों में सक्रिय तिब्बती संगठनों का कहना है कि आत्मदाह की यह लहर असल में चीनी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है और इसके द्वारा दलाई लामा को निर्वासन से वापस बुलाने की मांग भी की जा रही है। तिब्बत में आत्मदाह के 98 मामले हुए हैं जिनमें से ज्यादातर भिक्षुओं और भिक्षुणियों के द्वारा हुए हैं। तिब्बत के इन हालात को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन और अमेरिकी अधिकारियों के आह्वान पर चीन ने काफी नाराजगी के साथ प्रतिक्रिया दिखाई है और उसका कहना है कि यह उसके आंतरिक मामलों में दखल है।

दलाई लामा ने खुद यह आशावाद दिखाया है कि शी जिनपिंग की अगुवाई वाला नया चीनी नेतृत्व स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कदम उठाएगा। पिछले साल नवंबर में हू

सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ल्हासा–शिगास्ते रेलवे लाइन को इस साल पूरा कर लेगा चीन

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 23 जनवरी)

चीन सरकार ने 21 जनवरी को कहा है कि वह 253 किमी. लंबी ल्हासा–शिगास्ते रेल लाइन बिछाने का काफी काम कर चुकी है। यह रेलमार्ग क्विंघई–तिब्बत रेलमार्ग का ही विस्तार है और पूरी परियोजना का काम इस साल के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

चीनी की ऑनलाइन तिब्बत समाचार सेवा ईएनजी डॉट तिब्बत डॉट सीएन पर 21 जनवरी को जारी खबर में बताया गया है कि इस 'महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना' के तहत 82.3 किमी. लंबी रेल पटरी दिसंबर, 2012 तक ही बिछाई जा चुकी थी जो कुल परियोजना का 27.83 फीसदी है। इस रेलमार्ग का बड़ा हिस्सा पुलों और सुरंगों के रूप में होगा। खबर के मुताबिक इस पूरी परियोजना में 61,520 मीटर लंबी सुरंगों का भी निर्माण किया जा चुका है जो कुल सुरंग निर्माण कार्य का 85.13 फीसदी है।

इस रेल परियोजना के निर्माण की प्रारंभिक लागत 13. 3 अरब युआन (2.14 अरब डॉलर) है और इससे हर साल 83 लाख टन माल की ढुलाई हो सकेगी। अभी तक जो निर्माण कार्य पूरा हुआ है उसमें 7.06 अरब युआन (1.22 अरब डॉलर) खर्च हो चुके हैं।

काफी ऊंचे अक्षांश पर स्थित इस सेवा में 13 स्टेशन होंगे और यह दक्षिणी ल्हासा, क्युशुइ काउंटी और न्येमो काउंटी से होकर गुजरेगा। इस लाइन पर 120 किमी. प्रति घंटे से ज्यादा गति से भी गाड़ियां चल सकेंगी।

चीन के इस दावे को मिली चुनौती कि 'तिब्बत सबके लिए खुला है'

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 23 जनवरी)

ब्रिटिश संसद में लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों के उपाध्यक्ष श्री मैकमिलन स्कॉट ने 21 जनवरी को यूरोपीय संघ में चीन के राजदूत श्री वु हेलांग को चुनौती दी कि वे तिब्बत में ज्यादा लोगों को जाने दें और वहां के असल हालात की जानकारी लेने दें। तिब्बत का 1996 में दौरा करने वाले पहले विदेशी राजनीतिज्ञ स्कॉट ने करीब तीन साल की तिब्बत की पूरी तरह से बाहरी दुनिया के लिए बंदी को देखते हुए मांग की कि श्री वु 'अपने इस निराधार दावे कि 'तिब्बत विदेशी पर्यटकों के लिए खुला है' की पुष्टि के लिए यूरोपीय संसद के प्रतिनिधियों जाना सुगम बनाएं और हमें इस बात की इजाजत भी दें कि हम अपने तथ्यान्वेषी दलों को उन सुरक्षा बलों के साए के बगैर लोगों से मिलने के लिए भेज सकें जिन सुरक्षा बलों की तिब्बतियों की स्वाधीनता के बर्बर दमन में प्रमुख भूमिका है।"

"राजदूत वु हेलांग की टिप्पणी से यह छिपाने के लिए है कि तिब्बती समुदाय में हताशा का स्तर कितना ज्यादा है। चीन के एकाधिकारवादी शासन ने बेशर्म तरीके से इस बात की कोई जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है कि तिब्बत में चीन की कठोर नीतियों की वजह से ही करीब 100 तिब्बतियों ने आत्मदाह का दुःखद रास्ता अपनाया है और चीन सरकार की वजह से ही दलाई लामा को मजबूरन निर्वासन का सहारा लेना पड़ा है।"

स्कॉट का यह प्रत्युत्तर चीन के यूरोप में शीर्ष राजनयिक के इंटरव्यू के बाद आया है। हेलांग ने 21 जनवरी को द पार्लियामेंट डॉट कॉम को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा था, "मैं पूरी ईमानदारी से यूरोप के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि वे तिब्बत का दौरा करें ताकि वहां के सौंदर्य और वहां के लोगों के जीवन का अनुभव कर सकें। मेरा मानना है जो कुछ मैं यहां बता रहा हूं, आपका खुद अनुभव करना उससे ज्यादा विश्वसनीय होगा।"

इस इंटरव्यू में मुख्यतः वु ने तिब्बत में चीन की नीतियों का बचाव किया, जबकि इन्हीं नीतियों से फरवरी 2009 के बाद लगातार विरोध के कष्त्य में करीब 100 तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया है। स्कॉट ने कहा, "राजदूत वु हेलांग की टिप्पणी से यह छिपाने के लिए है कि तिब्बती समुदाय में हताशा का स्तर कितना ज्यादा है। चीन के एकाधिकारवादी शासन ने बेशर्म तरीके से इस बात की कोई जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है कि तिब्बत में चीन की कठोर नीतियों की वजह से ही करीब 100 तिब्बतियों ने आत्मदाह का दुःखद रास्ता अपनाया है और चीन सरकार की वजह से ही दलाई लामा को मजबूरन निर्वासन का सहारा लेना पड़ा है।" स्कॉट ने कहा कि "तिब्बत एक जेल में तब्दील हो गया है।"

आत्मदाह के मामलों में वु ने दावा किया था, "आत्मदाह की घटनाओं की गोपनीय तरीके से योजनाएं बनाने, उकसाने, आयोजित करने और इसे पूरा करने में कुछ विदेशी ताकतें शामिल रही हैं।" इसकी पुष्टि के लिए उनके पास बस इतना ही प्रमाण था कि ऐसी घटनाओं के तत्काल बाद 'दलाई गुट' ने "आत्मदाह के बारे में वीडियो, तस्वीरें और आत्मदाह करने वाले के विवरण जारी किए।"

चीनी अधिकारियों ने ऐसी हर घटना के बाद आत्मदाह करने वालों के परिवार वालों को प्रताड़ित, गिरफ्तार और दंडित किया है, लेकिन वु का दावा है कि, "हमें लोगों की जान जाने पर गहरा दुःख है और हम उनके परिवार के इस दुःख में उनके साथ हैं।" उन्होंने आत्मदाह करने वालों के द्वारा उठाए जाने वाले मसलों को खारिज करने की कोशिश की। आत्मदाह करने वाले लोगों का

कहना था कि तिब्बत में किसी भी तरह की धार्मिक आज़ादी नहीं है, भाषा और सांस्कृतिक अधिकारों, खासकर शिक्षा के बारे में अधिकारों से लोगों को वंचित किया जा रहा है। लेकिन वु का दावा है कि कानून के माध्यम से इन सभी अधिकारों की रक्षा की गई है। पर श्री स्कॉट ने उनके इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उनके संसद का तिब्बत पर गठित सांसदों का समूह "इस बारे में विश्वसनीय साक्ष्य हासिल कर रहा है कि तिब्बती संस्कृति, भाषा आदि को चीनी शासन लगातार व्यवस्थि तरीके से खत्म कर रहा है।"

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने तीन तिब्बती भिक्षुओं को रिहा करने का आह्वान किया

फायूल, 5 जनवरी

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत करने वाले संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपने एक बयान में तीन तिब्बती भिक्षुओं संगराब ग्यात्सो, येशी सांगपो और ड्राकसांग के गायब हो जाने पर चिंता जताते हुए उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की है।

इसके पहले फायूल ने यह खबर दी थी कि पूर्वी तिब्बत के चीनी अधिकारियों ने छामरु मठ के तीन भिक्षुओं को गिरफतार कर लिया है। पिछले साल नवंबर माह में सोल्हो के छाबछा क्षेत्र में हुए छात्रों के व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बारे में सूचनाएं भेजने में इनकी कथित भूमिका को लेकर यह गिरफ्तारी की गई थी।

चीनी सुरक्षा कर्मियों ने सुनग्रैब ग्यात्सो को 1 दिसंबर को गिरफ्तार किया, जबकि ड्रागसांग और येशे सांगपो को उनके मठ से इसके दो दिन बाद गिरफ्तार किया गया। बयान में कहा गया है कि इन भिक्षुओं को कहां रखा गया है और इनकी क्या हालत है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है।

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा, ''जेल की सजा और बंदियों को बैरकों में कैद रखना चरम उपाय हैं, लेकिन इनका मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ आम इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मानवाधिकार कार्यकर्ता ऐसी सूचनाओं को प्रसारित करने की कोशिश करते हैं जिनको शासन दबाना चाहता है।

बयान में कहा गया है, "हम ऐसे चलन से नाराज हैं जिससे यह पता चलता है कि चीन जनवादी गणतंत्र न केवल आज़ादी और न्याय के बारे में संदेशों पर पाबंदी लगा रहा है, बल्कि इस तरह की सूचनाओं को प्रसारित करने वाले लोगों को निशाना भी बना रहा है। हमने तीन भिक्षुओं को तत्काल रिहा करने और उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने की मांग की है।"

पिछले साल 26 नवंबर को छाबछा सोरिग लोबलिंग स्कूल के एक हजार से ज्यादा तिब्बती छात्रों ने चीन सरकार के खिलाफ एक बड़ी विरोध रैली निकाली। इस रैली में आज़ादी की मांग, सभी राष्ट्रीयताओं को समानता देने, भाषा की आज़ादी, सच के सम्मान और शासन की पुनर्स्थापना करने की मांगों से जुड़े नारे लगाए गए।

चीनी सशस्त्र बलों ने इस प्रदर्शन को तितर–बितर करने के लिए हिंसा का सहारा लिया जिसमें बहुत से युवा घायल हो गए और करीब 20 विद्यार्थियों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इसके बाद स्कूल की जबर्दस्त घेराबंदी कर दी गई और चीनी सुरक्षा बल विद्यार्थियों को अपने मां–बाप या रिश्तेदारों से मिलने से भी रोक लगाने लगे।

आरएसएफ को यह पता चला है कि विरोध प्रदर्शनों और आत्मदाह के मामलों की सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए हाल के महीनों में बहुत से तिब्बती भिक्षुओं को गिरफ्तार किया गया है और जेलों में डाल दिया गया है।

दलाई लामा के उपदेश सुनने वाले सैकड़ों तिब्बतियों को अब भी चीन ने हिरासत में रखा है

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 19 जनवरी)

जनवरी 2012 में भारत में दलाई लामा के कालचक्र उपदेश में हिस्सा लेने के बाद वापस लौटे सैकड़ों तिब्बतियों को चीन ने हिरासत में ले लिया था। इनमें से बहुत से लोगों को अब भी तिब्बत की राजधानी ल्हासा की जेल में रखा गया है। रेडियो फ्री एशिया की एक 17 जनवरी की अन्य खबर के मुताबिक अपने दुकान और मकान में दलाई लामा से जुड़ी वस्तुएं रखने वाले एक कारोबारी को दो साल के लिए जेल में डाल दिया गया है। एक तिब्बती नागरिक 55 वर्षीय जिग्मे तोपग्याल (जुनगार के नाम से भी पुकारे जाने वाले) को दो महीने के लिए राजनीतिक शिक्षण के लिए भेजा गया था। दलाई लामा के कालचक्र उपदेश का फायदा उठाकर लौटे सभी तिब्बतियों के लिए चीनी प्रशासन ने यह राजनीतिक शिक्षण अनिवार्य कर दिया है। काचलक्र को तिब्बती बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सशक्तिकरण शिक्षण के रूप में माना जाता है। हालांकि, जिग्मे के अपने परिवार के बीच वापस लौटने के 15 दिन के बाद ही 15 मई को चीनी पुलिस ने उनके घर और दुकान पर छापा मारा था और वहां से दलाई लामा के कालचक्र उपदेश के बारे में 15 डीवीडी और दलाई लामा की तस्वीरें जब्त कर लीं। तोपग्याल को पुलिस वाले अपने साथ लेते गए।

तोपग्याल का करीब दो हफ्ते तक कुछ पता नहीं चला, इसके बाद उनके परिवार को जानकारी मिली कि उन्हें चीनी पुलिस द्वारा थोपे गए सश्रम सजा के तहत ही दो साल के पुनर्शिक्षा कार्यक्रम का सामना करना पड़ रहा है। खबर के मुताबिक ल्हासा के गुत्सा हिरासत केंद्र के बाहर चिपकाई गई एक नोटिस

(1)

(2)

(10)

कैमरे की आं

1 पटना एयरपोर्ट पर 3 जनवरी को परमपावन दलाई लामा के पहुंचने पर उनक
कुमार। तिब्बती बौद्ध नेता पटना में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संघ द्वारा आयोजित एक
सदी में बौद्ध संघों की भूमिका'। (फोटोः परमपावन दलाई लामा का ब्यूरो, नई
2 कर्नाटक के मुंडगोड में स्थित ड्रेपंग लाची मठ में 17 जनवरी को "मन, मस्तिष्क अ
26वें मन एवं जीवन सम्मेलन में बोलते हुए परमपावन दलाई लामा। (फायूल
3 जयपुर के दिग्गी पैलेस में आयोजित जयपुर साहित्य समारोह के दौरान 24 ज
4 श्री वीरभद्र सिंह (बीच में) को तिब्बती थांगका पेंटिंग पेश करते हुए सिक्योंग ड
5 सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई के विद्यार्थी और कर्मचारी 23 जनवरी को परमपावन
6 श्री लालू प्रसाद यादव के साथ तिब्बती संसद का प्रतिनिधिमंडल
7 तिब्बती संसद के प्रतिनिधिमंडल के साथ भारतीय संसद के सदस्य रामजेठमल
8 कोलकाता, पश्चिम बंगाल के राजभवन में तिब्बती संसद के प्रतिनिधिमंडल के
9 ज्ञान प्रजन्या अंध आवासीय स्कूल के बच्चों को 22 जनवरी को गले लगाते हु
बच्चों के लिए यह आवासीय स्कूल 2001 में शुरू किया गया था और इसे एक
10 आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ

(9)

(8)

♦ आंखों देखी

(3)

(4)

(5)

की आंख से

पर उनका स्वागत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश
जित एक सेमिनार को संबोधित करने के लिए गए थे। इस सेमिनार का विषय था–'21वीं
ब्यूरो, नई दिल्ली)
मस्तिष्क और जड़–बौद्ध विचार और विज्ञान के बीच महत्वपूर्ण संवाद" विषय पर आयोजित
(फायूल फोटोः गेलेक पालसांग)
रान 24 जनवरी को बोलते हुए तिब्बती आध्यात्मिक नेता परमपावन दलाई लामा
सिक्योंग डॉ. लोबसांग सांगे (दाएं), साथ में कालोन सेरिंग ढोनडुप (बाएं) भी हैं।
परमपावन दलाई लामा का स्वागत करते हुए (फोटोः ओएचएचडीएल/जेरेमी रसेल

रामजेठमलानी।
ोमंडल के साथ राज्यपाल एम.के. नारायणन।
लगाते हुए परमपावन दलाई लामा। दृष्टि विकलांग
र इसे एक बौद्ध भिक्षु चलाते हैं। (फायूल फोटोः गेलेक पालसांग)
के साथ आंध्र के मुख्यमंत्री श्री किरण कुमार रेड्डी।

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(7)

(6)

से लोगों को यह जानकारी मिली। खबर के मुताबिक एक सूत्र ने बताया, "इस घोषणा में बताया गया है कि तोपग्याल पर यह आरोप लगाया गया है कि वह भारत में होने वाले कालचक्र शिक्षण में शामिल हुए और वहां से निषिद्ध सामग्रियां अपने साथ लेकर आए।"

तोपग्याल को बाद में ल्हासा के बाहर स्थित एक और हिरासत केंद्र तोलुंग हिरासत केंद्र ले जाया गया और आखिरकार 15 दिसंबर को उन्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत दी गई। परिवार वालों का पता चला कि हिरासत में रखे गए पहले 15 दिन में तोपग्याल की जमकर पिटाई की गई।

उन्हें पता चला कि तोलुंग हिरासत केंद्र में 350 लोगों को रखा गया है, जिनमें से ज्यादातर पूर्वी तिब्बत के खम और आमदो क्षेत्र के वे तिब्बती हैं जो भारत में कालचक्र शिक्षण में हिस्सा लेने के लिए गए थे। इनमें एक 16 वर्ष की लड़की सोनम ल्हामो भी शामिल है।

चीनी शासन वाले तिब्बत में 11 दिन में आत्मदाह की 3 घटनाएं

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 24 जनवरी)

चीनी शासन वाले तिब्बत में आत्मदाह की एक और घटना हुई है। इस तरह पिछले 11 दिनों में इस इलाके में विरोध प्रदर्शन की ऐसी यह तीसरी घटना है। इस घटना के साथ ही फरवरी 2009 से अब तक तिब्बत में आत्मदाह की अब तक 99 घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें 13 सितंबर, 2012 को एक 62 वर्षीय तिब्बती महिला द्वारा बीजिंग में किया गया आत्मदाह भी शामिल है जिसकी खबर बाहरी दुनिया को काफी देर से मिली। इस महिला का नाम पसांग ल्हामो है और यह क्विंघई प्रांत के युश काउंटी स्थित क्येगुदो की रहने वाली थीं।

खबर के मुताबिक एक 26 वर्षीय तिब्बती कोंछोग क्याब ने 22 जनवरी की दोपहर में गांसू प्रांत के सांगछू काउंटी में बोरा मठ के परिसर में खुद को आग लगा लिया। खबर के मुताबिक ग्यारलिंग गांव के मूल निवासी इस व्यक्ति का जलने से निधन हो गया। रेडियो फ्री एशिया की 22 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय तिब्बतियों ने उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए सौपने की मांग करते हुए ऐसा न होने पर स्थानीय थाने के सामने धरने पर बैठने की चेतावनी दी जिसके बाद पुलिस वाले उनके शरीर के अवशेष को दूर लेकर चले गए। शाम को बड़ी संख्या में स्थानीय तिब्बती नागरिक जमा हो गए, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए एक भी भिक्षु या आम आदमी को कोंछोग क्याब के घर नहीं जाने दिया और आदेश दिया कि उनके लिए कोई भी धार्मिक क्रिया नहीं की जानी चाहिए। निर्वासित तिब्बती प्रशासन की वेबसाइट तिब्बत डॉट नेट पर दी गई खबर के मुताबिक चीन ने तत्काल ही मठ के आसपास सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया और इसके बहुत से भिक्षुओं को हिरासत में ले लिया। चीन की इस कार्रवाई की तात्कालिकता से ऐसा लगता है कि इन भिक्षुओं को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया है कि वे आत्मदाह को रोकने में विफल रहे। क्याब अपने पीछे पत्नी और 10 माह की एक बेटी को छोड़ गए हैं।

चीन ने चार तिब्बती भिक्षुओं को जेल में डाला

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 23 जनवरी)

तिब्बत के सिचुआन प्रांत के नाबा प्रशासनिक क्षेत्र के बरखाम काउंटी की एक चीनी अदालत ने चार तिब्बती भिक्षुओं को 2 से 10 साल के लिए जेल की सजा सुनाई है। धर्मशाला स्थित तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र की 21 जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार भिक्षुओं को यह सजा जनवरी महीने के मध्य में किसी दिन सुनाई गई है।

स्थानीय तिब्बतियों का कहना है कि इन भिक्षुओं पर यह संदेह जताया गया कि पिछले साल 30 मार्च और 17 जुलाई को दो भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले आत्मदाह में इन्होंने सहयोग किया था।

ये चारों भिक्षु स्थानीय ग्यालरोंग सोदुन मठ से जुड़े हुए हैं। इनके नाम हैं–नामसे, यारफेल, एसोंग और लोबसांग सांगे। 18 वर्षीय नामसे को 10 साल के लिए, 18 वर्षीय यारफेल को छह साल के लिए, 22 वर्षीय एसोंग को ढाई साल के लिए और 19 वर्षीय लोबसांग को दो साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है।

पहले चीनी पुलिस ने 30 मार्च, 2012 को रात में मारे एक छापे में लोबसांग सांगे, यारफेल और नामसे को गिरफ्तार किया था। इसके बाद बाद 16 अगस्त को एसोंग को दो अन्य भिक्षुओं थुपवांग तेनजिन, 20 वर्ष, और राबतेन के साथ गिरफ्तार किया गया था। थुपवांग और राबतेन का अभी तक कोई पता नहीं है।

30 मार्च 2012 को 21 वर्षीय छिमे पालदेन और 22 वर्षीय तेनपा धारग्ये, जबकि 17 जुलाई 2012 को लोबसांग लोजिन ने आत्मदाह कर लिया था।

मेरे बेटे ने न्याय और स्वाधीनता के लिए जान दी है, मुझे कोई पछतावा नहीं है

(फायूल, 21 जनवरी, 2013)

"मेरे बेटे ने न्याय और तिब्बत की स्वाधीनता के लिए जान दी है। मुझे इसका रत्ती भर भी पछतावा नहीं है।" आत्मदाह करने वाले तिब्बती नागरिक ड्रबछोग के पिता क्यागपो ने उनको सांत्वना देने के लिए आए लोगों से यह बात कही।

ड्रबछोग (पहले उनका नाम सेरिंग फुंत्सोक बताय जा रहा था) ने 18 जनवरी को चीनी शासन के विरोध में पूर्वी तिब्बत के ख्युंगछू इलाके में खुद को आग लगा लिया। उनकी विरोध प्रदर्शन स्थल पर ही मौत हो गई, जिसके बाद चीनी सुरक्षा बल उनके पार्थिव शरीर को उठाकर पास के कस्बे बरखाम लेकर गए।

स्विट्जरलैंड में रह रहे एक तिब्बती सोनम ने फायूल को बताया कि उनके किसी परिवार जन को बताए बिना चीनी अधिकारियों ने बाद में उसी दिन ड्रबछोग का अंतिम संस्कार कर दिया।

अब इसके बारे में ज्यादा जानकारियां मिल रही हैं और ऐसा इनके मुताबिक ड्रबछोग ने ड्राछेन कस्बे के निकट ख्युंगछू इलाके में एक बास्केटबॉल मैदान के पास आत्मदाह किया है। इस मैदान और इसके आसपास के इलाके में अक्सर भीड़–भाड़ रहती है।

इस इलाके में रहने वाले कुछ सूत्रों के हवाले से सोनम ने बताया, "खुद को आग लगाने से पहले ड्रबछोग ने अपने हाथ प्रार्थना की मुद्रा में जोड़ते हुए कहा 'ग्यालवांग तेनजिन ग्यात्सो'।

फायूल को मिली एक तस्वीर में ड्रबछोग शरीर आग की लिपटों में घिरे होने के बावजूद सीधे बैठे हुए दिख रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि आत्मदाह विरोध प्रदर्शन के बाद भारी हथियारों से लैस चीनी सुरक्षा बल ड्राछेन कस्बे पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया। स्थानीय तिब्बती फिलहाल "आशंका और चिंता के तनावपूर्ण माहौल के बीच' जी रहे हैं।

धर्मशाला स्थित निर्वासन के कीर्ति मठ केंद्र के मुताबिक 28 वर्षीय ड्रबछोग अपने पीछे क्रमशः पांच और तीन साल की दो बेटियां और पत्नी रिग्पा को छोड़ गए हैं।

वर्ष 2009 के बाद अब तक तिब्बत में 97 से ज्यादा तिब्बतियों ने तिब्बत पर चीनी कब्जे के विरोध, तिब्बतियों के लिए स्वाधीनता और परमपावन दलाई लामा की तिब्बत में वापसी की मांग करते हुए खुद को आग लगा लिया है।

चीनी प्रशासन लगातार इन विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्वासित तिब्बतियों को जिम्मेदार ठहराता रहा है और उसने लगातार ऐसे कठोर कदम उठाए हैं जिनसे तिब्बत में स्थिति और गंभीर हुई है। आत्मदाहों को आपराधिक कार्रवाई बताने और इस तरह के विरोध प्रदर्शनों के बारे में जानकारी भेजने के आरोप में बहुत से तिब्बतियों की मनमाने तरीके से गिरफ्तारी की मानवाधिकार संगठनों ने आलोचना की है।

तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि पूरे वर्ष 2012 में आत्मदाह के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है। स्थानीय चीनी अधिकारियों ने सरकारी मशीनरी और 'कार्य दलों' को राजनीतिक शिक्षण अभियान चलाने और न केवल आत्मदाह करने वालों, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों और उनके गांव में रहने वाले लोगों पर भी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

संगठन ने उल्लेख किया है कि स्वतंत्र मीडिया, संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों और अंतर्राष्ट्रीय तथ्यान्वेषी दलों या पर्यटकों को तिब्बत के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा चीन सरकार ने "संचार माध्यमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और तिब्बत से बाहर सूचनाओं के प्रसार पर भी पूरी तरह से रोक लगी है।"

अटल बिहारी वाजपेयी

पूर्व प्रधानमंत्री

तिब्बत की आजादी

जब से चीन में कम्युनिस्ट शासन आया, च्यांग–काई–शेक के साथ बड़े मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध होते हुए भी भारत ने नये चीन का स्वागत किया और संसार के राष्ट्रों में उसे सम्मान का स्थान मिले इसके लिये हमने उनसे बड़ कर प्रयत्न किया। हमारे प्रयत्नों को देखकर कभी–कभी ऐसा लगा कि मुद्दई सुस्त है और गवाह चुस्त है। (हमने चीन की वकालत की क्योंकि हम समझते थे कि कम्युनिज़्म से हमारा मतभेद होते हुए भी यदि चीन की जनता उस मार्ग का अवलम्बन करती है तो यह उसकी चिंता का विषय है, और भिन्न–भिन्न जीवन पद्धतियों के होते हुए भी भारत और चीन मित्रता के साथ रह सकते हैं।)

लेकिन इस मित्रता को पहला आघात उस दिन लगा जब तिब्बत को चीन की सेनाओं ने 'मुक्त' किया। हमारे प्रधान मंत्री ने उस समय पूछा था कि तिब्बत को किससे मुक्त किया जा रहा है, तिब्बत किसी देश का गुलाम नहीं था। भारत तिब्बत का निकटतम पड़ोसी है। अतीत के इतिहास में अगर हम चाहते तो तिब्बत को अपने साथ मिलाने का प्रयत्न कर सकते थे, लेकिन आज जो चीन के नेता भारत विस्तारवादी होने का आरोप लगाते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि हमने कभी भी तिब्बत को अपने साथ मिलाने का प्रयत्न नहीं किया। तिब्बत छोटा है। लेकिन हमने उसके पृथक अस्तित्व का समादर किया। हमने तिब्बत की स्वतंत्रता का सम्मान किया, और हम आशा करते थे कि चीन भी ऐसा ही करेगा लेकिन कम्युनिस्टों के तरीके अलग होते हैं। उनके शब्दों की परिभाषायें अलग होती है। जब वह गुलाम बनाना चाहते हैं तो कहते हैं कि हम मुक्त करने जा रहे हैं, आज जब वह दमन कर रहे हैं तो कहते हैं कि सुधार करने जा रहे हैं। अगर कहीं सुधार करना है तो जिन्हें सुधारना हैं उनमें सुधार की प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए। सुधार ऊपर से नहीं लादा जा सकता।

लेकिन तिब्बत में जो कुछ हो रहा है वह सुधार नहीं है। 1950 के समझौते के अन्तर्गत तिब्बत की स्वायत्तता का चीन द्वारा समादर किया जाना चाहिए था, लेकिन चीन ने तिब्बत के अन्दरूनी मामलों में दखल दिया, चीन से लाखों की संख्या में चीनी तिब्बत में बसाये गये जिस से तिब्बत वासी अपने ही देश में अल्पसंख्या में हो जायें और आगे जा कर तिब्बत चीन का अभिन्न अंग बन जाये। तिब्बत से हजारों नौजवानों को चीन में भेजा गया, नये मजहब की शिक्षा प्राप्त करने के लिये, लेकिन जब वह लौट कर आये और चीनी नेताओं ने देखा कि उन पर असर नहीं हो रहा है, और उनका तिब्बती रंग नहीं मिटाया जा सकता, उनकी पृथकता कायम रहती है और अपनी जीवन–पद्धति की रक्षा करने का उनका उत्साह अमिट रहता है, तो उनके कान खड़े हुए और उन्होंने तिब्बत की जीवन–पद्धति को मिटाने का प्रयत्न किया। वर्तमान संघर्ष एक बड़े राष्ट्र द्वारा एक छोटे राट्र को निगलने की इच्छा के कारण उत्पन्न हुआ है।

तिब्बत पर चीनी प्रभुसत्ता स्वीकार कर भूल की

मेरा निवेदन है कि हमने जब तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता स्वीकार की तो हमने बड़ी गलती की। वह दिन बड़े दुर्भाग्य का दिन था। लेकिन गलती हो गयी और हम शायद यह समझते थे कि यह मामला हल हो जायेगा, नया संघर्ष पैदा नहीं होगा, और हम दूसरों को मौका नहीं देना चाहते थे कि वे हमारे और चीन के मतभेदों का लाभ उठायें। लेकिन परिणाम क्या हुआ? चीन ने केवल तिब्बत के ही साथ हुए समझौते को नहीं तोड़ा, बल्कि उस समझौते की पृष्ठभूमि में भारत के साथ जो समझौता हुआ था, उसका भी उल्लंघन किया। पंचशील की घोषणा कहाँ गयी ? जो पंचशील के दावें करते हैं उनका कहना है कि पंचशील के अन्तर्गत लोकतंत्र और अधिनायकवाद साथ–साथ जीवित रह सकते हैं। अगर कम्युनिस्ट साम्राज्य के अन्तर्गत तिब्बत के धर्मप्रिय और शान्तिप्रिय लोग अपनी विशिष्ट जीवन–पद्धति की रक्षा नहीं कर सकते, तो यह कहना कि इतने बड़े संसार में कम्युनिज़्म और डिमॉक्रेसी साथ–साथ रह सकते हैं इसका कोई अर्थ नहीं होता। हम चीन के अन्दरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहते मगर तिब्बत चीन का अन्दरूनी मामला नहीं है। चीन बंधा हुआ है तिब्बत की स्वयत्तता का समादार करने के लिये, तिब्बत के अन्दरूनी मामलों में दखल न देने के लिए। लेकिन वह समझौता टूट गया और मैं समझता हूँ कि अब भारत को भी, भारत सरकार को भी अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिए। समझौते दोनों तरफ से चलते हैं, दोनों तरफ से पालन होते हैं। अगर चीन ने समझौता तोड़ दिया, तो हमें अधिकार है कि हम अपनी परिस्थिति पर फिर से विचार करें। क्या कारण है कि तिब्बत की जनता को उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है ?

तिब्बत क्यों स्वतंत्र नहीं रह सकता ? कहते है कि

पहले स्वतंत्र नहीं था, तो क्या जो देश पहले स्वतंत्र नहीं था, उस को स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं हो सकता ? क्या जहाँ पहले गुलामी थी, वहाँ अब भी गुलामी रहनी चाहिए ? अगर अल्जीरिया की स्वतंत्रता की आवाज का हम समर्थन कर सकते हैं, और वह समर्थन करना फ्रांस के अन्दरूनी मामलों में दखल देना नहीं है, तो तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन चीन के अन्दरूनी मामलों में दखल कैसे हो सकता है ? अभी मेरे मित्र श्री खडिलकर ने कहा कि देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, जो तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन करती है। मैं उनसे अपना मतभेद प्रकट करना चाहता हूँ। मैं एक छोटी–सी पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, लेकिन हमारी पार्टी तिब्बत की स्वतंत्रता की हिमायत करती है। तिब्बत की आजादी की आवाज कितने लोग उठाते हैं, इससे यह आवाज सही है या गलत, इसका निर्णय नहीं हो सकता। चीनी साम्राज्यवादी अपने पशुबल के द्वारा तिब्बत की स्वतंत्रता की आवाज को आज दबा सकते हैं, मगर स्वतंत्रता की पिपासा को मिटाया नहीं जा सकता। दमन उस आन्दोलन में आग में घी का काम करेगा और आज नहीं तो कल तिब्बत की जनता अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करके रहेगी।

मगर प्रश्न यह है कि हम उसके लिये क्या कर सकते हैं ? मैंने निवेदन किया कि हमने 1950 में गलती की। अब हमें उसका दण्ड भुगतना पड़ रहा है। लेकिन समय है प्रायश्चित करने का, गलती को पहचानने का। मैं प्रधानमंत्री जी से इस बात की आशा करता हूँ कि वह इस अवसर पर देश की करोड़ों जनता का सही प्रतिनिधित्व करेंगे। मुट्ठी–भर हमारे मित्रों को छोड़ कर सारा भारत इस प्रश्न पर एकमत है कि तिब्बत में जो कुछ हो रहा है, वह नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या यह सम्भव है कि तिब्बत चीनी राज्य के अन्तर्गत अपनी स्वायत्तता का उपभोग कर सके ? मुझे तो लगता है कि कम्युनिस्ट पद्धति और स्वायत्तता दोनों परस्पर विरोधी बाते हैं। कम्युनिस्ट राज्य में स्वायत्तता नहीं हो सकती। माओ–त्से–तुंग ने 1930 में कहा था कि हमने ऐसा संविधान बनाया है कि अगर कोई हमसे बाहर जाना चाहेगा, तो बाहर जा सकेगा। तिब्बती तो बाहर जाने की बात नहीं करते थे। वे तो अपना पृथक अस्तित्व रखना चाहते थे, मगर उन्हें इसकी भी इजाजत नहीं दी गई।

उन्होंने यह भी कहा कि हम ऐसे फूल को खिलता हुआ देखना चाहते हैं, जिसमें हजारों पंखुड़ियाँ होगी। हजारों की तो बात अलग रही, तिब्बत की कोमल कली को भी कुचला जा सकता रहा है। जो तिब्बत में साम्राज्यवाद बन कर बैठे हैं, वे हम पर आरोप लगा रहे हैं। हमने कभी तिब्बत को भारत में मिलाने का प्रयत्न नहीं किया। हमने जहाँ चीनी को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान देने की वकालत की थी, वहाँ हम तिब्बत को स्थान देने की वकालत कर सकते थे। यूक्रेन सोवियत संघ का अंग है, मगर वह संयुक्त राष्ट्र संघ में अलग स्थान पर बैठा है। तो क्या तिब्बत चीन के साथ होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ में अलग स्थान नहीं भर सकता था ? मगर हमने चीन की मित्रता के लिए ऐसा नहीं किया। हमें उस मित्रता का क्या प्रतिदान मिला ? हम मित्रता आज भी चाहते हैं, मगर उस मित्रता का महल तिब्बत की आजादी की लाश पर नहीं खड़ा नहीं किया जा सकता। अन्याय को देखकर हम आँखें बन्द नहीं कर सकते। यह भारत की परम्परा रही है और इसी परम्परा में हमारे प्रधानमंत्री ने देश की विदेश नीति का संचालन किया है कि जहाँ कहीं अन्याय होगा, मानवता का हनन होगा, अत्याचार होगा, हम अपनी आवाज उठायेंगे, हम सत्य की भाषा को बोलेंगे और निर्भीक होकर हम पददलित होने वाले अधिकारों का संरक्षण करेंगे। आज तिब्बत कसौटी है नेहरू जी की नीतिमत्ता की, तिब्बत कसौटी है भारत सरकार की दृढ़ता की, तिब्बत कसौटी है चीन की पंचशील–प्रियता की। पंचशील की घोषणायें करने से, पंचशील की जो भावना है, उसका आदर नहीं होगा। पंचशील की कसौटी आचरण है। हमारे प्रधानमंत्री कितना भी संयम से काम लें, लेकिन अगर उससे तिब्बत की समस्या हल नहीं होती, तो हमें मानना पड़ेगा कि उस नीति में थोड़ी–सी दृढ़ता, थोड़ी–सी सक्रियता लाने की आवश्यकता है।

हम मित्रता आज भी चाहते हैं, मगर उस मित्रता का महल तिब्बत की आजादी की लाश पर नहीं खड़ा नहीं किया जा सकता। अन्याय को देखकर हम आँखें बन्द नहीं कर सकते। यह भारत की परम्परा रही है और इसी परम्परा में हमारे प्रधानमंत्री ने देश की विदेश नीति का संचालन किया है कि जहाँ कहीं अन्याय होगा, मानवता का हनन होगा, अत्याचार होगा, हम अपनी आवाज उठायेंगे, हम सत्य की भाषा को बोलेंगे और निर्भीक होकर हम पददलित होने वाले अधिकारों का संरक्षण करेंगे।

दलाई लामा तिब्बत में रहें, या जायें, यह कोई बड़ा सवाल नहीं है। यह तो तिब्बती आपस में तय करेंगे। लेकिन तिब्बत एक कसौटी है बड़े राष्ट्र द्वारा छोटे राष्ट्र को निगलने की। अगर छोटे देश इस तरह से निगले जायेंगे, तो संसार की शांति कायम नहीं रह सकती है। दक्षिण–पूर्वी एशिया में अनेक देश ऐसे हैं जिनमें चीनी बहुसंख्या में निवास करते हैं। तिब्बत के कारण उन सब देशों में एक आशंका की लहर उत्पन्न हो गई है। जहाँ तक भारत का सवाल है, हम पर तो चीन की शनि–दृष्टि दिखाई देती है। चीन के नक्शों में हमारा प्रदेश उनका बताया गया है।

चीन के कम्युनिस्टों ने च्यांग–काई–शेक को तो निकाल दिया, मगर उनके नक्शों को रख लिया। अगर वे चाहते तो नक्शों को भी निकाल सकते थे। और हमारे कम्युनिस्ट दोस्तों ने तो वह नक्शे देखें ही नहीं हैं। मुझें उनकी बात पर विश्वास नहीं होता। लेकिन यह चीन का अप्रत्यक्ष है भारत के लिए। उत्तर प्रदेश के दो स्थानों पर चीनी कब्जा जमा कर बैठे हैं। ये घटनायें आने वाले संकट की ओर संकेत करती हैं। हमें आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है, मगर हमें दृढ़ नीति अपनानी चाहिए।

एक बात मैं और निवेदन करूँगा। दलाई लामा भारत में आये हैं। वे स्वतंत्रता के लड़ाकू है, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके कारण उनको अपना देश छोड़कर भारत में आना पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि अपने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई भारत में चलाने का अधिकार होना चाहिए। उनके ऊपर जो बन्धन लगाये गये हैं, वे यद्यपि सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन उन बन्धनों का ढीला करने की आवश्यकता है। अगर हमारे देशभक्त अंग्रेजी राज्य के दिनों में दूसरे देशों में जाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न कर सकते थे और हमारी आँखों में सम्मान का स्थान प्राप्त कर सकते थे, तो कोई कारण नहीं कि दलाई लामा को भी इस बात की छूट न दी जाये।

दलाई लामा अगर चीन के साथ समझौता करने में सफल हों, और हमारे प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में कोई मध्यस्थता कर सकें तो इससे बढ़कर देश की जनता को कोई और आनन्द नहीं होगा। लेकिन अगर चीन के नेताओं को सीधी राह पर नहीं लाया जा सकता, राजनीतिक या कूटनीतिक दबाव से उन्हें नहीं समझाया जा सकता और बर्मा, लंका और इंडोनेशिया के जनमत को जाग्रत करके, संगठित करके, प्रभावी रूप से उसका प्रकटीकरण करके, अगर चीन पर असर नहीं डाला जा सकता, तो भारत के सामने इसके सिवा कोई विकल्प नहीं रहेगा कि हम दलाई लामा को छूट दे दें कि वह अपने देश की आजादी के लिए प्रयत्न करें।

भारत नौजवान तिब्बत की स्वतंत्रता को अमूल्य समझते है– इसलिए नहीं कि तिब्बत के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं, अपितु इसलिए कि हम गुलामी में रह चुके हैं, हम गुलामी का दुख और दर्द जानते हैं, हम आजादी की कीमत जानते हैं – उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाये। तिब्बत की जनता अगर आजादी के लिए संघर्ष करती है तो भारत की जनता उसके साथ होगी। हम अपनी सहानुभति उनको देंगे और हम चीन से भी आशा करें कि वह साम्राज्यवाद की बाते न करें। साम्राज्यवाद के दिन लग गये। किन्तु यह नया साम्राज्यवाद है। इसका खतरा यह है कि यह एक क्रान्ति के आवरण में आता है, यह इन्कलाब की पोशाक पहन कर आता है, यह नई व्यस्था का नारा लगाता हुआ आता है, मगर है यह उपनिवेशवाद, है यह साम्राज्यवाद। अतीत में हमें गोरों के साम्राज्यवाद से लड़ते रहे लेकिन अब यह पीलों साम्राज्यवाद भी प्रकट हो रहा है विश्व की छत पर। हमें दृढ़ता के साथ उसका भी मुकाबला करना चाहिए।

(लोकसभ, 8 मई 1959)

चीनी कलाकार तिब्बत में आत्मदाह करने वालों को दर्शा रहे हैं

(गिलियन वोंग, एपी, बीजिंग, 13 जनवरी)

बीजिंग के कलाकार लिउ यि कई ऐसे श्वेत–श्याम पोर्ट्रेट तैयार कर रहे हैं जिन्हें वे जानते हैं कि कभी भी किसी चीनी गैलरी में नहीं दिखाया जा सकेगा। उन्हें विविध विषयों–मर्द और औरतों, युवा एवं महिला, मुस्कराते और उदास लोग–इन सभी में एक चीज आम हैः वे तिब्बती हैं जो चीन की दमनकारी नीतियों के विरोध में खुद को आग लगा रहे हैं। लिउ उन सभी करीब सौ आत्मदाह करने वाले तिब्बतियों का पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, जिन्होंने पिछले तीन साल में आत्मदाह किए हैं, ताकि हाल के इतिहास में अग्निमय विरोध प्रदर्शनों की सबसे बड़ी लहर का एक दस्तावेजी साक्ष्य बन सके। हर बार कूची चलाने के साथ ही लिउ एक हार्दिक विनती भी करते हैंः इस तरह लोगों का जलना बंद होना चाहिए।

करीब 40 वर्ष के मष्दुभाषी पेंटर ने कहा, "जब मैं पेंटिंग कर रहा था, तो मैं सोच रहा थाः बहुत हुआ, अब कोई और ऐसा न करे। रुको, बहुत हो चुका।" काफी हद तक एक वर्जित विषय को छूने के मामले में लिउ अपने समकालीन चीनियों से काफी आगे हैं। हान चीनी बहुसंख्यक वर्ग के बहुत कम एक्टिविस्ट ने इस तरह खुलकर बोला है। इस तरह की हिम्मत दिखाने वाले प्रमुख कानूनी विद्वान जु झियांग भी शामिल हैं।

इस चुप्पी के पीछे तिब्बत आंदोलन के प्रति हान चीनियों की उदासीनता या बैर ही है, जबकि कुछ उदारवादी हान एक्टिविस्ट भी चीन के एकाधिकारवादी नियंत्रण से खीजे हुए हैं। इस तरह की चुप्पी के लिए क्षमा मांगते हुए शु ने हाल में एक आलेख में लिखा था, "हम खुद पीड़ित हैं।"

लेकिन बहुसंख्यक हान जनता में से बहुत से लोग आत्मदाह की घटनाओं को चीन से अलग होने की कोशिश मानते हैं और वह इस पर अचरज जताते हैं कि आखिर तिब्बती अपने इलाके में रेल संपर्क, एक्सप्रेसवे, मकान और कारखाने

बनाने के रूप में हुए विकास के लिए सरकार के प्रति ज्यादा कष्तज्ञ क्यों नहीं हैं।

हान चीनी लोग असाधारण घास के मैदानों और याक पालने वाले नोमैड वाले तिब्बत को एक निर्जन और अज्ञात क्षेत्र के रूप में देखते हैं, लेकिन यह किसी को भी आकर्षित नहीं करता। जबकि साल भर चीनी पर्यटक बीजिंग के एक प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध मंदिर में जाते हैं और वहां अगरबत्तियां जलाते हैं और साथ ही शहर के कई दुकानों से सस्त तिब्बती आभूषणों या शिल्पकृतियों की खरीद करते हैं।

यद्यपि हान चीनी एक्टिविस्ट द्वारा तिब्बत के नाजुक पर्यावरण की रक्षा की वकालत बढ़ती जा रही है, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक मसलों से दूर रहते हैं और तिब्बतियों के पेट्रोल पीकर धार्मिक आज़ादी तथा स्वायत्तता की मांग करते हुए जल जाने पर चुप्पी साधे रहते हैं। लिउ को उम्मीद है इसमें बदलाव आएगा। उन्होंने कहा, "मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि हर कोई इसे विचारधारा या जातीय तरीके से नहीं देखेगा, लेकिन मानवीय आधार पर इस पर ध्यान देगा।"

लिउ गाढ़े ब्रशस्ट्रोक का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल श्वेत–श्याम रंग में अपने विषय के चेहरों को क्लोज–अप बनाना पसंद करते हैं, जिससे उनके हर झुर्री, शिकन, त्योरी चढ़ने या मुस्कराहट की अंतरंग छवि दिख सके। उनके ज्यादातर विषय दर्शकों को टकटकी लगाकर देखने पर मजबूर कर देते हैं, बिल्कुल बांध लेते हैं, खासकर तब जब इन पोर्ट्रेट को एक एकल, बड़े मोंटाज के रूप में व्यवस्थित कर पेश किया जाता है।

लिउ ने हाल में एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकारों को अपनी पेंटिंग दिखाने के बाद दिए इंटरव्यू में कहा, "आप देख सकते हैं कि इनमें से बहुत से तिब्बती युवा हैं।" उनका यह काम उनके स्टुडियो में लगाया गया है और एक साथ आठ पोर्ट्रेट की कुल पांच पंक्तियां हैं। उन्होंने निचली पंक्ति में दो बच्चों जैसे चेहरे को दिखाते हुए कहाः "यह 15 वर्ष का है, वह 16 वर्ष का है।"

तिब्बती कवि और एक्टिविस्ट वुएजर का कहना है कि ये आत्मदाह "दुःख की अभिव्यक्ति का एक तरीका हैं और पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन हैं।"

वुएजर ने एक इंटरव्यू में कहा, "बहुत से हान बुद्धिजीवी राजनीतिक मांगों को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। उनके हिसाब से तिब्बत चीन का हिस्सा है। उनका सोचना है कि यदि आप कोई राजनीतिक मांग करते हैं तो इसका मतलब है कि आप आज़ादी चाहते हैं।"

तिब्बती आंदोलनकारियों का कहना है कि यह विरोध प्रदर्शन चीन द्वारा भारी सुरक्षा बलों की तैनाती, धर्म पर पाबंदी और उनके प्रिय आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की निंदा करने से पैदा होने वाली कुंठा की वजह से हो रहे हैं। चीन का कहना है कि इस इलाके में चीनी आर्थिक सहायता प्रयासों को कमजोर करने के लिए दलाई लामा इन आत्मदाहों को हवा दे रहे हैं।

नवंबर माह में आत्मदाह के द्वारा विरोध प्रदर्शनों की संख्या और बढ़ गई, जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी अगली पीढ़ी के नेताओं को स्थापित करने के लिए एक सभा का आयोजन किया।

वुएजर ने कहा, "इस चुनौतीपूर्ण समय में, हमें न केवल अंतरराष्ट्रीय समुदाय के आकर्षण की जरूरत है, बल्कि चीनी समाज द्वारा गौर करने की भी। यह महत्वपूर्ण है कि हान चीनी बुद्धिजीवी भी कुछ कहें और इस समस्या के बारे में साफ तौर से अभिव्यक्त करें।"

उन्होंने कहा कि गहराई से देखें तो बहुत से हान लोग असल में तिब्बती जीवन शैली और उसके आध्यात्मिक दर्शन से खुद को अलग महसूस करते हैं।

सुश्री वुएजर ने कहा, "तिब्बती और हान संस्कषति इस मामले में अलग है कि एक आध्यात्मिक है तो दूसरा भौतिकवादी। यह अंतर वास्तव में एक ऐसी खाई है जिसे भरना मुश्किल है।" उन्होंने कहा, "बहुत से हान लोगों को अब भी यह भरोसा नहीं होता कि तिब्बती इस तरह की आध्यात्मिक इच्छाओं के बारे में कैसे सोचते हैं, जैसे खुद को आग लगा लेने की।"

तिब्बत आंदोलन का समर्थन करने वाले हान चीनियों में बीजिंग के मानवाधिकार कार्यकर्ता हू जिया और लिउ शाशा शामिल हैं जिन्होंने सरकार की दमनकारी नीतियों को बंद करने की मांग करते हुए आत्मदाह के बारे में ट्वीटर पर संदेश प्रसारित किए हैं।

कानून के विद्वान शु ने तो और भी जोखिमपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने अक्टूबर महीने में सख्त नियंत्रण वाले अबा प्रशासनिक क्षेत्र में आत्मदाह करने वाले तिब्बती नांगड्रोल के परिवार वालों से मिलने का प्रयास किया।

न्यूयॉर्क टाइम्स में पिछले महीने लिखे एक लेख में शु ने लिखा, "मुझे खेद है कि हम हान तिब्बती चुप बैठे हुए हैं, जब नांगड्रोल और उनके साथी तिब्बती स्वाधीनता के लिए मर रहे हैं। हम खुद के पीड़ित हैं, अलगाव, आपसी मतभेद, घृणा और विनाश के बीच रह रहे हैं। जबकि हमारी भूमि साझी है। यह हमारा साझा घर, हमारी साझी जिम्मेदारी और साझा सपना है और यह हमारी साझी मुक्ति भी होगी।"

आधे हान, आधे मांचू और तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायी कलाकार लिउ जैसे लोगों के लिए उनकी इस परियोजना में एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक तत्व भी है।

लिउ ने अपने पोर्ट्रेट के बारे में बताया, "जब मैं इनकी पेंटिंग कर रहा था, मुझे यह हमेशा लगता था कि मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं और सज्जन, दयालु होता जा रहा था। वे लोग दूसरे लोगों पर हमले नहीं कर रहे, वे पूरी तरह से खुद को बलिदान कर रहे हैं।"

निर्वासित तिब्बतियों को अब भी वापस तिब्बत जाने की उम्मीद

(विशाल गुलाटी, आइएएनएस, धर्मशाला, 17 जनवरी)

भारत में आधी सदी से भी ज्यादा समय तक रहने के बाद भी उत्तर भारत के पहाड़ी शहर धर्मशाला में रहने वाले तिब्बतियों में अपनी मातृभूमि को देखने की हसरत कम नहीं हुई है। यहां 1960 के दशक से ही यहां रह रही अस्सी वर्ष से ऊपर की ओर हो चुकी एक महिला लामत्सो ने कहा, "मैं उस जमीन पर अब भी कदम रखने की इच्छा रखती हूं जो काफी समय पहले मैं छोड़कर आई थी।"

बर्फ से ढंकी धौलाधर पर्वतीय श्रृंखला में स्थित इस विलक्षण कस्बे मैकल्योडगंज में लामत्सो अपने परिवार के साथ 1960 के दशक के शुरुआती वर्षों में आईं थीं, जब तिब्बत में चीनी सेना के हमले के बाद तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई को निर्वासित होकर भारत आना पड़ा था।

धर्मशाला के ऊपर स्थित मैकल्योडगंज में स्थित सुगलांगखांग के मंदिर में एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए भावुक लामत्सो ने कहा, "मैं पूर्वोत्तर तिब्बत के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। मुझे घास के मैदानों, बर्फ से ढके पहाड़ों और अपने ग्रामीण समुदाय की काफी याद आती है।" लामल्सो मैकल्योडगंज के इस मंदिर में हर दिन सुबह पूजा के लिए आती हैं।

मैक्ल्योडगंज निर्वासित तिब्बती सरकार का मुख्यालय है। भारत में करीब एक लाख निर्वासित तिब्बती रह रहे हैं। 1960 के दशक में ही भारत आई अस्सी से ऊपर की हो चुकी एक और महिला देछेन ने कहा, "मैं अपने निधन से पहले तिब्बत में मेरे पहले घर में लौटना चाहती हूं।" उन्होंने एक अनुवादक के माध्यम से बताया, "हर निर्वासित तिब्बती एक दिन अपने घर लौटने की उम्मीद करता है। मैं भारत की आभारी हूं जहां मैंने अपनी जवानी के ज्यादातर दिन गुजारे हैं।"

अपने जन्मभूमि की प्रिय यादों के साथ 86 वर्षीय देछेन ने निर्वासन में पूरी एक पीढ़ी को बड़ा किया है और चाहती हैं कि वे सब उनके साथ तिब्बत लौटें। उन्होंने कहा, "हमने अपने बच्चों और पोते–पोतियों को भारत में बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए संघर्ष किया है। अब उन्हें अपनी जनता की सेवा के लिए लौटना होगा।"

हालांकि भारत में जन्मे और पले–बढ़े तिब्बती अपनी पुरानी पीढ़ी के मुकाबले ज्यादा उम्मीद भरे लगते हैं। लोकप्रिय मिस तिब्बत सौंदर्य प्रतियोगिता कार्यक्रम के निर्माता–निर्देशक लोसांग वांगयाल ने कहा, "तिब्बत में रहने वाले तिब्बती आज नही तो कल स्वाधीनता की किरण देखेंगे ही। तिब्बत में आत्मदाहों की बढ़ती संख्या उनकी पीड़ा की हद को बयां करती है।"

उन्होंने एक समाचार एजेंसी को बताया, "अग्निमय विरोध प्रदर्शनों से यह पता चलता है कि ऐसी असहनीय परिस्थितियों में जीने से अच्छा तिब्बती मर जाना पसंद कर रहे हैं।"

निर्वासित तिब्बती सरकार के लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित पहले प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे ने कभी सपने में भी अपना घर लौटना नहीं देखा है। उन्होंने एक समाचार एजेंसी को बताया, "यह हमारा सपना, आकांक्षा और संघर्ष है।" 43 वर्षीय सांगे ने अगस्त 2011 में 74 वर्षीय भिक्षु और विद्वान सामदोंग रिनपोछे के बाद निर्वासित तिब्बती सरकार की इस कुर्सी पर बैठे हैं। रिनपोछे इस पद पर 10 साल रहे। दलाई लामा द्वारा राजनयिक और राजनीतिक मामलों से अलग हो जाने के बाद प्रधानमंत्री के पद को ज्यादा अहमियत मिल गई है।

उन्होंने कहा, "आध्यात्मिक नेता ने जब अपनी सरकार को चुने हुए नेतष्त्व को सौंपा तो हर कोई दलाई लामा के बगैर तिब्बती सरकार के आगे चलने को लेकर आशंकित था। लेकिन अब हम यह गर्व से कह सकते हैं कि उनके आशीर्वाद से तिब्बती आंदोलन और मजबूत हो रहा है।"

पुरानी पीढ़ी की कठोर मेहनत को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि तिब्बत आंदोलन की बुनियाद काफी मजबूत है। उन्होंने कहा, "मैंने चीन सरकार को साफ संदेश दिया है, जो अभी तक इस गलतफहमी में थी कि दलाई लामा के बाद तिब्बत आंदोलन खत्म हो जाएगा।" तिब्बत मसले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सांगे दलाई लामा की मध्यम मार्ग नीति का अनुसरण कर रहे हैं जिसमें चीन के भीतर ही वास्तविक स्वायत्तता की मांग की गई है। उन्होंने कहा, "लोकतंत्र और अहिंसा दो ऐसे सिद्धांत हैं जिनसे हम कभी भी समझौता नहीं कर सकते।" लेकिन वह वार्ता में भी भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा, "हम किसी भी समय, कहीं भी चीन से वार्ता करने को तैयार हैं।"

यहां तक कि तिब्बत से 1959 में बचकर भारत आए दलाई लामा को भी अपने घर वापस जाने की उम्मीद है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, "मैं इस मामले में आशावादी हूं कि एक दिन तिब्बत वापस लौटूंगा। तिब्बत बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है। इसके अलावा मैं चीन से अलग भी नहीं होना चाहता।"